

नौकरशाहों को मोदी का संदेश: दफ्तरों से बाहर निकलें, युवाओं और विश्वविद्यालयों तक पहुंचें



रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष नौकरशाहों को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार और युवाओं के बीच संवाद केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से युवाओं तथा विश्वविद्यालयों के साथ सीधे जुड़ाव बढ़ाने और नीति निर्माण में नई पीढ़ी की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह निर्देश 20 अगस्त को हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिए गए। प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था में विभागों के अलग-अलग दायरों में काम करने वाली 'साइलो'

संस्कृति को बड़ी चुनौती बताया। उनका जोर इस बात पर रहा कि अलग-अलग विभाग आपसी समन्वय बढ़ाएं और जमीनी स्तर पर परिणाम देने वाली व्यवस्था तैयार करें।

युवाओं से संवाद बढ़ाने का निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की बड़ी युवा आबादी केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति और विकास प्रक्रिया की सक्रिय भागीदार बन सकती है। विश्वविद्यालयों को इस संवाद का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने से शोध, नवाचार, रोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़े फैसलों में छात्रों और शिक्षाविदों की वास्तविक भागीदारी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर वे एक करोड़ युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं। अब असली परीक्षा नौकरशाही की है। निर्देश जारी करना आसान है, लेकिन उसका असर तभी दिखेगा जब सचिवालयों की फाइलों से निकलकर अधिकारी विश्वविद्यालयों के परिसरों, प्रयोगशालाओं और युवाओं के बीच पहुंचेंगे।

सवाल यही है-क्या नौकरशाही युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी मानेगी, या उन्हें देश की नीतियां गढ़ने वाला भागीदार भी बनाएगी?

होटल सयाजी के किचन में मिले कॉकरोच-चूहे, 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग तारीख

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

इंदौर/बौद्धिक प्रतिकार। इंदौर के प्रतिष्ठित होटल सयाजी में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। दिल्ली की खाद्य विभाग की टीम के साथ इंदौर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने होटल के किचन, भंडारण कक्ष और खाद्य सामग्री की जांच की। निरीक्षण के दौरान करीब 66 किलो नॉनवेज खाद्य सामग्री बिना पैकिंग तारीख के मिली। जांच में पाया गया कि होटल में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री को एक ही शीत भंडारण कक्ष में रखा गया था। समुद्री खाद्य, चिकन और मटन भी एक साथ रखे मिले। कई खाद्य पदार्थों के लिए निर्धारित तापमान बनाए रखने में भी लापरवाही सामने आई। उबले आलू पर अवधि समाप्त होने की तारीख की टैगिंग मिली, जबकि कुछ ट्रेट्रापैक रिसते हुए पाए गए। पैकड कुल्फी पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर दर्ज नहीं था। वहीं, जमे हुए मिठाई उत्पाद को होटल के मेन्यू में आइसक्रीम के नाम से दर्शाया गया था। कई खाद्य सामग्री बिना लेबल के मिली।

सबसे गंभीर स्थिति स्वच्छता व्यवस्था की रही। किचन और भंडारण क्षेत्रों में कॉकरोच, चूहों



की लीद और चूहे पाए गए। फर्श और दीवारों में दरारें थीं। जंग लगी सामग्री के साथ खाद्य तैयारी वाले मंच पर भी जंग मिली। सड़े टमाटर-आलू और मूंगफली में फंगस मिला। इसके अलावा कई खाद्य सामग्री दीवार से सटाकर और बिना पैलेट के सीधे जमीन पर रखी गई थीं। पैलेट के नीचे भी गंदगी मिली। ग्रेवी कमरे के तापमान पर रखी थी और गीले-सूखे कचरे के लिए अलग व्यवस्था नहीं मिली। अब सवाल यह है कि इतने बड़े होटल के किचन में खाद्य सुरक्षा के बुनियादी मानकों की ऐसी अनदेखी लंबे समय तक कैसे होती रही। विभाग की आगे की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी।

बुर्के की आड़ में 2 करोड़ के गहने पार, 1.5 किलो सोना लेकर फरार

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सराफा बाजार स्थित विश्वास ज्वेलर्स में बेहद शांति तरीके से करीब 1.5 किलो सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए। चोरी गए सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक, बुरखा पहने एक महिला पहले दुकान में पहुंची। कुछ देर बाद उसके साथ दो अन्य महिलाएं और टोपी-मास्क लगाए दो पुरुष भी आ गए। पांचों ने करीब 20 से 25 मिनट तक ग्राहक बनकर गहने देखे और दुकान के कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी। इसी दौरान एक कर्मचारी का ध्यान दूसरी ओर जाते ही एक महिला काउंटर के नीचे बैठ गई और फाटक के भीतर हाथ डालकर सोने का बॉक्स बाहर खींच लिया। उसने बॉक्स बुरखे में छिपाया और साथियों के साथ दुकान से बाहर निकल गई। सीसीटीवी में चोरी का यह पूरा तरीका रिकॉर्ड हुआ है। चौकाने वाली बात यह है कि चोरी के बाद आरोपी तत्काल भागे नहीं। टोली कुछ देर बाद दोबारा दुकान के सामने से गुजरी और यह सुनिश्चित किया कि उनका पीछा तो नहीं

गड्डों का शहर बना इंदौर, सरकार का मुंह बंद, नेता खामोश, नौकरशाह बेपरवाह

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

इंदौर में बारिश कम हुई, लेकिन सड़कों पर गड्डों की बारिश जरूर हो गई। शहर के कई इलाकों में सड़कें इस कदर टूट चुकी हैं कि आधा किलोमीटर का रास्ता भी वाहन चालकों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। सड़क पर डामर कम और गड्डे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम बारिश के दौरान नई तकनीक से पेचवर्क कर गड्डे भरने का दावा कर रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि मरम्मत के बावजूद सड़कें गड्डामुक्त नहीं हो पा रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सोमवार को गड्डे की वजह से एक बाइक सवार की जान भी चली गई।

सबसे बड़ा सवाल

यह है कि सरकार का मुंह बंद क्यों है? नेता खामोश क्यों हैं और नौकरशाह कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? जनता रोज इन टूटी सड़कों से गुजर रही है, वाहन खराब हो रहे हैं और हादसों का खतरा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से सिर्फ मरम्मत के दावे सुनाई देते हैं। हर साल सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सड़कें इतनी



जल्दी क्यों टूट जाती हैं? क्या निर्माण की गुणवत्ता की जांच सिर्फ कागजों पर होती है? क्या ठेकेदारों की जवाबदेही तय होती है? और यदि सड़क बनाने के कुछ समय बाद ही गड्डे निकल आए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बताने वाले जिम्मेदारों को अब सड़कों की तस्वीर भी देखनी चाहिए। शहर की चमकती तस्वीरों के पीछे गड्डों से भरी सड़कें छिपाई नहीं जा सकतीं। जनता पूछ रही है- गड्डे कौन भरेगा और जवाबदेही किसकी तय होगी?

MP: पुराने पत्थर, वही स्थापत्य और राजस्थान के हुनरमंद कारीगर... उज्जैन में लौट रहा 1000 साल पुराना मंदिर

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में करीब एक हजार साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारी ने शहर की प्राचीन स्थापत्य विरासत को फिर चर्चा में ला दिया है। मंदिर के निर्माण में पुराने पत्थरों, पारंपरिक स्थापत्य शैली और राजस्थान के कुशल कारीगरों की मदद ली जा रही है, ताकि नए निर्माण में भी मंदिर का मूल स्वरूप और ऐतिहासिक पहचान बरकरार रहे।

पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आधुनिक निर्माण शैली के बजाय पारंपरिक शिल्प और वास्तु तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है। पुराने मंदिर के बचे हुए पत्थरों और स्थापत्य अवशेषों को संरक्षित करते हुए उन्हें नए निर्माण में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान से बुलाए गए विशेषज्ञ कारीगर पत्थरों की नक्काशी और पारंपरिक जोड़ तकनीक पर काम करेंगे।

इस परियोजना को केवल मंदिर निर्माण



नहीं, बल्कि उज्जैन की ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मंदिर का स्वरूप ऐसा रखने पर जोर है, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक इमारत नहीं बल्कि प्राचीन स्थापत्य की अनुभूति हो। हालांकि, इतनी पुरानी धरोहर के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा सवाल ऐतिहासिक प्रमाणिकता का है। पुराने पत्थरों

का सही उपयोग, मूल स्थापत्य की पहचान और संरक्षण के मानकों का पालन कितना हुआ—इस पर विशेषज्ञों की निगरानी बेहद महत्वपूर्ण होगी। उज्जैन में मंदिरों और प्राचीन स्मारकों की लंबी श्रृंखला के बीच यह प्रयास सफल रहा तो धार्मिक पर्यटन के साथ शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती मिल सकती है।

“सरकार ने हमें

धोखा दिया”, हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर भड़के छात्र; आज 24

जिलों में पुतला दहन

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां रद्द होने के बाद संकट में आ गई थीं। करीब 450 अभ्यर्थियों को इसका सीधा लाभ मिलने की बात सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्र इसे अपने साथ धोखे के रूप में देख रहे हैं। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने आरोप लगाया है कि सरकार के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मंच ने शुक्रवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। दरअसल, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था।

हैदराबाद में रफ्तार का कहर: एस्टन मार्टिन की टक्कर से युवती की मौत, सांसद के बेटे पर केस



हैदराबाद के माधापुर इलाके में तेज रफ्तार लगजरी कार की टक्कर से 26 वर्षीय युवती भारती मुखी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश से जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजुष को मामले में आरोपी बनाया है। हादसा 16 अगस्त को इर्नोबिट मॉल के पास हुआ था। पुलिस के मुताबिक भारती मॉल में सेल्सवुमन के रूप में काम करती थीं। वह एक सहकर्मी के साथ खाना लेने गई थीं और वापस काम पर लौटते समय सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान एस्टन मार्टिन डीबीएक्स707 ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर सिर की चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और संजुष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता

की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण मौत से संबंधित है। पुलिस ने जांच के दौरान शराब और नशीले पदार्थों की जांच के लिए नमूने भी लिए हैं। हालांकि, रिपोर्टों में संजुष की गिरफ्तारी को लेकर विरोधाभासी जानकारी सामने आई है। कुछ रिपोर्टों में गिरफ्तारी की बात कही गई है, जबकि अन्य में पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने और गिरफ्तारी न होने की जानकारी है। इसलिए फिलहाल मामले की कानूनी स्थिति को लेकर आधिकारिक पुलिस पुष्टि को ही अंतिम माना जाना चाहिए। हादसे ने एक बार फिर शहरों में तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा के साथ यह सवाल भी खड़ा किया है कि प्रभावशाली परिवारों से जुड़े मामलों में जांच और कानून की कार्रवाई कितनी निष्पक्ष रहती है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान: शाहगंज पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज

बुधनी। शाहगंज में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय भ्रमण कार्यक्रम और जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शाहगंज पहुंचे और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। वहीं कार्यक्रम से पहले प्रेम-सुंदर फाउंडेशन की ओर से 30 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए।

हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 30 हजार रुपये की नई छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ किया गया। शाहगंज के कृषक भवन में आयोजित पहले कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी इंग्लिश माध्यम के 30 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। यह कार्यक्रम प्रेम-सुंदर फाउंडेशन की ओर से आयोजित

किया गया। संस्था चौहान के माता-पिता की स्मृति में संचालित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत भी की गई। योजना के तहत 10वीं और 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने वाले पात्र हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दिए जाने की बात कही गई। इस पहल का उद्देश्य हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों के साथ शिविर में पहुंचे नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं

का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। योजनाओं का लाभ दिलाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने कई हितग्राहियों से वन-टू-वन चर्चा भी की। शारदा अहिरवार ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले 10 हजार रुपये का ऋण लिया और अब 25 हजार रुपये का ऋण लेकर अपना व्यवसाय स्थापित किया है। वहीं चंद्रप्रकाश ने उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण स्वीकृत होने की जानकारी दी। जितेंद्र और भागीरथ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास की सभी किश्तें मिल चुकी हैं और उनका पक्का मकान तैयार हो गया है। शाहगंज के इस शिविर में कुल 68 आवेदन प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया। शाहगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक ओर जनसमस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया, वहीं मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की सौगात भी दी गई।

तीन साल की शर्त बदली, अब एक साल वकालत से न्यायिक सेवा का रास्ता

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नई दिल्ली। न्यायिक सेवा में प्रवेश की तैयारी कर रहे कानून के विद्यार्थियों और युवा वकीलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा बदलाव किया है। न्यायालय ने सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य तीन वर्ष की वकालत की शर्त घटाकर एक वर्ष कर दी है। यह बदलाव उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं। नए ढांचे में न्यायालय ने व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। चयनित अभ्यर्थियों



को नियुक्ति से पहले एक वर्ष का गहन प्रशिक्षण राज्य न्यायिक अकादमी में

करना होगा। इसके बाद एक वर्ष की संरचित विधिक सहायक अवधि होगी। इसमें पहले छह महीने प्रधान जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के साथ और अगले छह महीने संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन काम करना होगा।

अर्थात केवल परीक्षा पास कर लेना तत्काल नियमित न्यायाधीश बनने की गारंटी नहीं होगी। चयन के बाद प्रशिक्षण और न्यायालयीन कार्य का व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य रहेगा।

पुराने नियम से बड़ा बदलाव-मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए तीन वर्ष की वकालत अनिवार्य की थी। उस

समय न्यायालय ने कहा था कि अदालत की वास्तविक कार्यप्रणाली का अनुभव न्यायिक अधिकारी के लिए जरूरी है। अब पुनर्विचार के बाद न्यायालय ने व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण के बीच नया संतुलन बनाया है। एक वर्ष की वकालत के साथ चयन के बाद दो वर्ष की प्रशिक्षण-आधारित व्यवस्था लागू होगी।

31 मार्च 2027 तक संक्रमणकालीन राहत- नए नियम लागू होने तक कानून स्नातकों को संक्रमणकालीन राहत दी गई है। इस अवधि में जारी होने वाली संबंधित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पूर्व अनुभव की शर्त से राहत मिलेगी।

अविनाश रेड्डी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, छह ठिकानों पर छापे

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

हैदराबाद/कडप्पा। वाईएसआर कांग्रेस के कडप्पा सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने हैदराबाद और कडप्पा जिले में कुल छह स्थानों पर तलाशी ली। इनमें हैदराबाद के कोकापेट स्थित अविनाश रेड्डी के



आवास और उनके पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी से जुड़े परिसरों के अलावा विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों के ठिकाने भी शामिल बताए गए हैं। ईडी की यह कार्रवाई 15 मार्च 2019 को हुई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से जुड़े धनशोधन मामले में हो रही

जांच का हिस्सा है। एजेंसी अब इस मामले में कथित वित्तीय लेन-देन और धन के स्रोत की पड़ताल कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक जांच में कथित चार करोड़ रुपये के लेन-देन का पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि रकम का स्रोत क्या था, पैसा किन लोगों तक पहुंचा और कथित तौर पर इसका हत्या की साजिश से क्या संबंध था। तलाशी का दायरा

केवल अविनाश रेड्डी तक सीमित नहीं रहा। हत्याकांड में आरोपी बताए गए सुनील यादव, देविरेड्डी शिवशंकर रेड्डी और एर्रा गंगिरेड्डी से जुड़े परिसरों पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि, ईडी की तलाशी अपने आप में किसी व्यक्ति के अपराधी होने का प्रमाण

नहीं है। जांच पूरी होने और अदालत में आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब निगाह इस बात पर है कि तलाशी में ईडी को कौन से दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड मिलते हैं और आगे की कार्रवाई क्या होती है।

देहरादून में निवेश के नाम पर बड़ा खेल: क्रिप्टो-फॉरेक्स के जाल में सैकड़ों लोग, करोड़ों की रकम फंसी

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

देहरादून। देहरादून में क्रिप्टोकॉरेसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों को कथित तौर पर ऊंचे रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये जुटाने का मामला सामने आया है। हालिया शिकायत के मुताबिक, देहरादून क्षेत्र के करीब 140 से 160 लोग इस नेटवर्क से प्रभावित बताए जा रहे हैं और रकम करीब 12 करोड़ रुपये तक पहुंचने का आरोप है। आरोप है कि लवीश चौधरी उर्फ नवाब अली और उससे जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूहों, बैठकों और सेमिनारों के जरिए निवेशकों को जोड़ा। बोटब्रो, यॉर्कर एफएक्स, टीएलसी कॉइन और माइन क्रिप्टो जैसे ऑनलाइन मंचों के जरिए स्वचालित क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर महीने करीब 5 से 6 प्रतिशत रिटर्न का भरोसा दिलाए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

शुरुआत में निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए भुगतान किया गया, लेकिन बाद में रकम निकालने की सुविधा कथित तौर पर बंद कर दी

गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी विदेश चला गया। पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद रायपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच में बैंक खातों, डिजिटल साक्ष्यों और कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। चौकाने वाली बात यह है कि देहरादून में इसी नेटवर्क से जुड़े करीब 25 करोड़ रुपये की कथित ठगी का एक अन्य मामला पहले भी सामने आ चुका है और उसकी जांच विशेष कार्यबल को सौंपी गई है।

पुलिस सूत्रों के हवाले से इसे देशभर में फैले बड़े निवेश नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है।

सवाल सिर्फ निवेशकों की रकम का नहीं है। सवाल यह है कि ऊंचे और लगभग तय रिटर्न का लालच दिखाकर इतने बड़े नेटवर्क को स्थानीय स्तर पर प्रचार, सेमिनार और निवेश जुटाने की छूट कैसे मिलती रही? अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल रकम का पता लगाना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क, उसके स्थानीय एजेंटों और धन के अंतिम ठिकाने तक पहुंचना है।



लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लोगों को उच्च न्यायालय से जुड़ी न्यायिक सेवाएं अपने क्षेत्र के करीब उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लद्दाख के लिए अलग उच्च न्यायालय नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख



उच्च न्यायालय दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के मामलों की सुनवाई करता है। लद्दाख में खंडपीठ स्थापित होने से स्थानीय नागरिकों, वकीलों और अन्य पक्षधारों को हर मामले में जम्मू या श्रीनगर की ओर जाने की जरूरत कम हो सकती है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर न्याय तक पहुंच आसान होने के रूप में देखा जा रहा है। भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम और विशाल क्षेत्र होने के कारण लद्दाख में न्यायिक सुविधाओं तक पहुंच हमेशा चुनौती रही है। खंडपीठ बनने के बाद उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर कराने का रास्ता आसान होगा।

सरकार का यह कदम लद्दाख में प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

इससे न्यायिक मामलों में समय और यात्रा का खर्च कम होने की उम्मीद है। हालांकि, खंडपीठ के प्रभावी संचालन के लिए स्थान, न्यायाधीशों की उपलब्धता, कर्मचारियों और आवश्यक आधारभूत ढांचे जैसे मुद्दों पर आगे की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय लद्दाख के लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को उनके और करीब लाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

संध्या में अकेले माता-पिता: परिवार बचा तो समाज बचेगा

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार वह व्यवस्था है, जिसमें जीवन के सबसे कमजोर पड़ाव पर व्यक्ति को यह भरोसा रहता है कि उसके अपने उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज यही भरोसा टूट रहा है। सोनीपत के वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग पिता की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियों और नाती-नातिनों का अंतिम संस्कार में शामिल न होना महज एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक चरित्र का कठोर आईना है। बेटियों ने वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखना चुना—यह सुविधा का चरम है या संवेदनाओं का पतन? बेशक, हर मामले के पीछे परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। दूरी, नौकरी, स्वास्थ्य, पारिवारिक विवाद या अन्य मजबूरियाँ किसी संतान को अंतिम समय में पहुंचने से रोक सकती हैं। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर पूरी पीढ़ी को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं हमें बेचैन क्यों नहीं करतीं?

आज समय की कीमत रिश्तों से अधिक आय में नापी जा रही है। संयुक्त परिवार टूटे, शहर बड़े, नौकरियाँ बदलीं और जीवन की गति तेज हुई। माता-पिता धीरे-धीरे घर के सदस्य से जिम्मेदारी में बदल दिए गए। शुरुआत होती है—‘समय नहीं मिलता’ से और अंत होता है—‘वृद्धाश्रम ही बेहतर है’ पर। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमने इस अकेलेपन को सामान्य मानना शुरू कर दिया है। जिन माता-पिता ने बच्चों

को खड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया, उन्हीं के जीवन की संध्या में समाज के पास उनके लिए संस्थागत इंतजाम तो हैं, लेकिन अपनापन घटता जा रहा है। यह समस्या केवल बेटियों या बेटों की नहीं है। यह पूरी व्यवस्था की समस्या है। बाजार ने स्त्री और पुरुष दोनों से उत्पादक बनने की अपेक्षा की, लेकिन परिवार ने भावनात्मक श्रम का मूल्य तय नहीं किया।

नतीजा सामने है—कमाई बढ़ी, सुविधा बढ़ी, लेकिन साथ घटता गया। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा, डे-केयर और सामुदायिक केंद्रों के साथ ऐसी रोजगार नीतियाँ बनानी चाहिए, जिनमें माता-पिता की देखभाल को भी सामाजिक जिम्मेदारी माना जाए। कंपनियों को अभिभावक देखभाल अवकाश जैसी सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन कानून रिश्ते पैदा नहीं कर सकता। रिश्ते घर में ही बचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ‘कुटुंब प्रबोधन’ जैसे अभियानों के माध्यम से परिवार-केंद्रित चेतना पर जोर देना इसी व्यापक चुनौती की ओर संकेत करता है। ऐसे प्रयास तभी सार्थक होंगे, जब परिवार स्वयं यह तय करे कि बुजुर्ग बोल नहीं, उसकी स्मृति, अनुभव और जड़ों का हिस्सा हैं। आज सवाल तीन बेटियों का नहीं है। सवाल यह है कि कल जब हम बूढ़े होंगे, तब हमारी संतान हमारे पास होगी या सिर्फ वीडियो कॉल? यदि इस प्रश्न का उत्तर हमें डराता है, तो परिवार बचाने की शुरुआत आज से करनी होगी। क्योंकि जिस समाज में माता-पिता की अंतिम यात्रा भी ‘सेवा’ के हवाले हो जाए, वहां विकास के आंकड़े बहुत कुछ बता सकते हैं—लेकिन समाज कितना मानवीय बचा है, यह नहीं।

“भारतीय महिला होने का क्या मतलब?” राहुल गांधी ने महिलाओं से मांगा जवाब, बोले— अपनी आवाज बताइए



रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय महिलाओं से उनके अनुभव, संघर्ष, सपनों और अपनी पहचान को लेकर सीधे सवाल किया है। गुरुवार को जारी वीडियो में उन्होंने पूछा कि “एक भारतीय महिला होने का क्या मतलब है?” साथ ही महिलाओं से कहा कि वह समाज या परिवार की सोच नहीं, बल्कि अपनी खुद की आवाज सामने रखें। राहुल गांधी ने महिलाओं से उनके सामने आने वाली मुश्किलों, सामाजिक दबाव, बाधाओं, नजरिए और सपनों के बारे में अपनी कहानी साझा करने की अपील की। उनके मुताबिक महिलाओं के वास्तविक अनुभवों को समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से उनके सामने मौजूद चुनौतियों की तस्वीर साफ होती है। यह पहल राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से भी जुड़ी है। 22 अगस्त को पुणे में होने वाले कार्यक्रम में केवल महिला श्रोता शामिल होंगी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा केंद्रित रहेगी। राहुल गांधी ने महिलाओं से मिले कुछ जवाब भी साझा किए, जिनमें सामाजिक नियंत्रण, पितृसत्ता, भेदभाव और परिवार की अपेक्षाओं जैसे मुद्दे सामने आए। कई महिलाओं ने बताया कि उनके जीवन के फैसलों पर ‘चिंता’ के नाम पर नियंत्रण रखा जाता है। अब राहुल गांधी ने देशभर की महिलाओं से जवाब मांगा है। सवाल राजनीतिक मंच से आगे बढ़कर व्यक्तिगत अनुभवों पर है—एक महिला की पहचान समाज तय करेगा या वह खुद अपनी आवाज से अपनी कहानी लिखेगी?

फुटपाथ पर दुकान, सड़क पर आदमी-फिर भी शहर स्मार्ट है

दैनिक “भास्करदर्पण”

www.dainikbhaskardarpan.com

किसी शहर की पहचान चौड़ी सड़कों और तेज वाहनों से नहीं, आम आदमी के आसान पैदल चलने से होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2047 में ‘राइट टू वॉक’ का प्रस्ताव इसी अधिकार को केंद्र में लाता है। यह केवल फुटपाथ सुधार की योजना नहीं, बल्कि सड़क पर बढ़ते वाहन वर्चस्व को चुनौती है। सुरक्षित, निर्बाध, छायादार और सर्वसुलभ पैदल मार्गों का सिटीवाइड नेटवर्क, पैदल-केवल सड़कें, मल्टी-यूटिलिटी जोन और एक्टिव ट्रेवल एरिया इसकी प्रमुख कड़ियाँ हैं। व्यस्त बाजारों, धरोहर क्षेत्रों और चौबीस घंटे सक्रिय इलाकों को प्राथमिकता देकर पैदल यात्रियों को शहर की योजना के केंद्र में रखा गया है।

यमुना और नालों के किनारे ग्रीनवे तथा पेलिकन क्रॉसिंग नेटवर्क को और सुरक्षित बनाएंगे। दिल्ली में यह पहल सफल होती है तो इसे राजधानी तक सीमित न रखकर देश के हर शहर की शहरी नीति में पैदल अधिकार को अनिवार्य जगह देनी चाहिए। शहर की तरक्की का सबसे कमजोर सबूत उसका वह फुटपाथ है, जिस पर आदमी चल ही न सके। देश के अधिकांश शहरों में फुटपाथ हैं, लेकिन वे पैदल यात्री के हिस्से में नहीं आते। कहीं कारें उन

पर खड़ी हैं, कहीं दुकानें और खोमचे फैल गए हैं, तो कहीं बिजली के खंभे और निर्माण सामग्री रास्ता रोकते हैं। बची-खुची जगह भी टूटी, ऊबड़-खाबड़ या बीच में खत्म हो जाती है, इसलिए पैदल यात्री को सड़क पर उतरना पड़ता है। बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए यह असुविधा नहीं, रोज का खतरा है। दिल्ली में औसत पैदल ट्रिप केवल 1.6 किलोमीटर है, जबकि गैर-मोटर चालित यात्राएं कुल यात्राओं का 42 प्रतिशत हैं। संदेश साफ है—लोग चलना चाहते हैं, शहर ने उनके कदमों की जगह छीन ली है। इसलिए ‘राइट टू वॉक’ केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं, हर भारतीय शहर की अनिवार्य शहरी नीति बननी चाहिए।

पैदल रास्ता केवल दो कदमों के बीच की खाली जगह नहीं, शहर के सार्वजनिक जीवन की पहली चौखट है। उसे सिर्फ सीमेंट की पट्टी मानना शहर को आधा देखना है। मल्टी-यूटिलिटी जोन इसी सोच को बदलने का रास्ता है। बैठने की जगह, पेयजल, शौचालय, बच्चों की देखभाल कक्ष, स्ट्रीट वेंडरों के लिए तय स्थान और साइकिल शेयरिंग जैसी सुविधाएं फुटपाथ को चलने की जगह से आगे बढ़ाकर जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र बना सकती हैं। सार्वजनिक परिवहन से इसका सीधा जुड़ाव अंतिम मील की परेशानी भी घटाएगा। दिल्ली का यह मॉडल

30 सितंबर तक राम मंदिर परिसर का अधिकांश निर्माण पूरा, 2027 में तैयार होगा रामकथा संग्रहालय

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण को लेकर बड़ी समयसीमा सामने आई है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूरे करने का लक्ष्य है। इसके बाद निर्माण में लगी प्रमुख एजेंसियों की भूमिका धीरे-धीरे समाप्त होगी

और 30 अक्टूबर तक एलएंडटी तथा टाटा के कर्मचारी निर्माण स्थल से हट जाएंगे। हालांकि, परिसर में सभी काम सितंबर तक समाप्त नहीं होंगे। ऑडिटोरियम और अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण इसके बाद भी जारी रहेगा।

संग्रहालय को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आधुनिक तकनीक पर आधारित 20 गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें रामकथा और भारतीय धार्मिक-सांस्कृतिक

विरासत को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। मिश्रा के अनुसार संग्रहालय की गैलरियों की कहानी और पटकथा तैयार की जा चुकी है। इन्हें दृश्य माध्यम में बदलने के लिए आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की तकनीकी मदद ली जा रही है। एक गैलरी में देश के प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने और दूसरी में भगवान राम के वनगमन से जुड़ी नदियों एवं प्रसंगों को प्रदर्शित करने की योजना है। इसके अलावा राम मंदिर

परिसर की करीब 3400 मीटर लंबी बाहरी दीवार का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। सुरक्षा उपकरणों की स्थापना में इसके बाद लगभग दो महीने लग सकते हैं। यानी सितंबर में मंदिर परिसर के मुख्य निर्माण का बड़ा चरण पूरा होगा, जबकि 2027 में रामकथा संग्रहालय और अन्य सुविधाओं के साथ अयोध्या के इस विशाल धार्मिक-सांस्कृतिक परिसर का अगला अध्याय आकार लेगा।

पूर्वी सीमा पर केंद्र की पैनी नजर, एक महीने में दूसरी बार उत्तर बंगाल पहुंचे अमित शाह, सुरक्षा एजेंडे पर मंथन



सिलीगुड़ी गलियारे से तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक सुरक्षा का नया खाका

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

नई दिल्ली। पूर्वी भारत की संवेदनशील सीमाओं को लेकर केंद्र सरकार ने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर बंगाल पहुंचे हैं। करीब एक महीने के भीतर उनका यह दूसरा दौरा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर केंद्र की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। दौरे के केंद्र में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी गलियारा है। यह संकरा भू-भाग पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। घुसपैठ, तस्करी,

हथियारों की आवाजाही, मादक पदार्थों के कारोबार और सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकना प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार अब केवल जवानों की तैनाती तक सीमित रहने के बजाय तकनीकी निगरानी, खुफिया सूचनाओं के बेहतर इस्तेमाल और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दे रही है। उत्तर बंगाल की भौगोलिक स्थिति इसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। ऐसे में छोटी सी सुरक्षा चूक भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। अमित शाह का लगातार उत्तर बंगाल पहुंचना संकेत देता है कि केंद्र अब इस पूरे क्षेत्र को सामान्य प्रशासनिक मुद्दे की बजाय रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देख रहा है। असली चुनौती यह होगी कि समीक्षा और बैठकों के फैसले जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर ईडी की नजर, सरकारी धन से लेकर कथित काले धन तक की पड़ताल

494 करोड़ के निर्माण खर्च और सांसद-विधायक निधि के इस्तेमाल के दावों ने बढ़ाई जांच की गंभीरता

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

रामपुर। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद निर्माण में लगी रकम के स्रोत को लेकर बड़े सवाल सामने आए हैं। ईडी की हालिया तलाशी में सरकारी ठेकों की रकम को कथित तौर पर निजी ठेकेदारों के जरिए ट्रस्ट या विश्वविद्यालय से जुड़े निर्माण कार्यों तक पहुंचाए जाने के वित्तीय सुराग मिलने की बात सामने आई है। जांच का एक अहम बिंदु विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च हुई रकम है। उपलब्ध जांच संबंधी रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट की ओर से निर्माण लागत करीब 45 करोड़ रुपये बताई गई थी, जबकि जांच में 59 भवनों की अनुमानित लागत करीब 494 करोड़ रुपये सामने आने का दावा किया गया है। यही बड़ा अंतर अब रकम के वास्तविक स्रोत और उसके इस्तेमाल को लेकर जांच का केंद्र है। मामले को और गंभीर बनाता है सरकारी धन से जुड़े लेनदेन का सवाल। जांच रिपोर्टों में आठ सरकारी विभागों से जुड़े धन के विश्वविद्यालय निर्माण में इस्तेमाल की पड़ताल का उल्लेख है। इसके अलावा सांसद और विधायक



निधि से करीब 4.57 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों में लगाए जाने की जानकारी भी सामने आ चुकी है। हालांकि इन निधियों के इस्तेमाल को लेकर पहले न्यायिक स्तर पर आपत्तियां उठीं और रकम वापस किए जाने की बात भी सामने आई थी। ईडी अब ठेकेदारों, निर्माण

कंपनियों, ट्रस्ट से जुड़े लोगों और कथित दानदाताओं के बीच हुए लेनदेन की कड़ियां जोड़ रही है। एजेंसी का फोकस यह पता लगाने पर है कि सरकारी ठेकों से हासिल रकम का कोई हिस्सा वास्तव में ट्रस्ट या विश्वविद्यालय तक पहुंचा या नहीं और यदि पहुंचा तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या था।

जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर उठते सवाल

रणजीत टाइम्स
ranjeettimes.com

प्रति मिनट की कार्यवाही पर करीब ढाई लाख रुपये के खर्च की बर्बादी के पुराने आंकड़े दोहराते हुए संसद की गिरती उत्पादकता पर फिर चिंता जताई जा रही है। मानसून सत्र में मात्र 19 प्रतिशत कामकाज ही हो पाया और 173 कार्य घंटे बर्बाद हो गए। दो महत्वपूर्ण विधेयक मात्र 14 मिनट की चर्चा में पारित कर दिए गए तो 11 बिना किसी चर्चा के। जाहिर है कि संसद में काम कम हुआ और हंगामा ज्यादा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार भी होना ही चाहिए। हमारी संसदीय राजनीति में हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा रही है। बेशक हंगामे की शुरुआत अक्सर विपक्ष की ओर से ही होती है, मगर अकारण तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान उसके कारणों के निवारण की मांग करता है, लेकिन हम कारणों से ही मुंह चुरा लेने के अभ्यस्त हो चले हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष की भूमिकाएं बदलते ही भाव-भंगिमाएं बदल जाना गैर-जिम्मेदार और अवसरवादी राजनीति ज्यादा है। 2014 से पहले नेता-प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सदन चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी तथा संसदीय गतिरोध को भी संसदीय राजनीति का संवैधानिक उपकरण बताते थे, पर सत्ता पाने के बाद भाजपा का सोच

बदल गया। तब संसदीय गतिरोध के लिए भाजपा को कठघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब अपनी वैसी ही भूमिका को सर्वथा लोकतांत्रिक ठहरा रही है। संसदीय गतिरोध और उसके जरिये सड़क की राजनीति का एजेंडा तय करने की प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन उसका लगातार बढ़ते जाना खतरनाक है। पहले जो विरोध वैचारिक या मुद्दा आधारित होता था, अब वह दलगत रंजिश में बदल गया लगता है। इसी कटुता का परिणाम और प्रभाव है कि एक-दूसरे पर टिप्पणी करते हुए भाषाई मर्यादा भी तार-तार की जा रही है। संसद के मानसून सत्र जैसा हंगामा पहली बार नहीं हुआ। नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्वकाल में हर्षद मेहता कांड पर भी संसद में ऐसे ही दृश्य देखे गए थे। मनमोहन सिंह के समय टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले पर संसद कई दिनों तक ठप रही थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। वह राष्ट्र हित था और यह राष्ट्र विरोध। ऐसा अतार्किक सोच दलों-नेताओं का हो सकता है, जनता का नहीं। इस बार तो हंगामे का संकेत सत्र की शुरुआत के साथ ही मिल गया था। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र एवं युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन 20 जुलाई को संसद मार्च का एलान भी किया जा चुका था।

सरकार की विलंबित सक्रियता का भी परिणाम रहा कि संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई और धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद बाद के घटनाक्रम और उसके चलते हुए राजनीतिक नुकसान से नहीं बचा जा सका। सरकार की उसी नाकामी से विपक्ष के हाथ ऐसा मुद्दा लग गया, जिसने सत्तापक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया। जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव चंद महीने ही दूर हैं, तब विपक्ष उस मुद्दे को हाथ से कैसे चले जाने देता, जिसने उसे उस 'जेन जी' के हितों का चैंपियन बनने का मौका दे दिया, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है और जिसका समर्थन हाल तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी ताकत रही? फिर एक इस्तीफे पर ही न रुक जाने की आक्रामक राजनीति भी विपक्ष ने भाजपा से ही सीखी है। मनमोहन सिंह के दौर में तमाम आरोपों के आधार पर ही भाजपा ने एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे करवाए थे। इसलिए धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आना ही था। संसदीय गतिरोध में भी समाधान का रास्ता निकालने की कवायद सदन के सभापति और संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों के भी विपक्ष से संबंध सहज नहीं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में शुरू हुई संसद में 'हल्ला ब्रिगेड' की खतरनाक

परंपरा तोड़ने की जरूरत किसी ने भी नहीं महसूस की। आज भी सदन में दोनों ही ओर हंगामेबाजों की कमी नहीं, लेकिन यदि संसदीय कार्य मंत्री भी उसी ब्रिगेड का सदस्य बनते दिखें तो विपक्ष से संवाद की पहल कौन करेगा? पिछली लोकसभा में विपक्षी सांसदों के रिकार्ड निलंबन के बाद से स्पीकर ओम बिरला भी विपक्ष का विश्वास लगभग खो चुके हैं। सत्रावसान के बाद उनकी चाय पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। जाहिर है, यह सब संसदीय लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता, लेकिन क्या आपको किसी के चेहरे पर शिकन भी नजर आती है? नहीं, क्योंकि संसद चलने न चलने से न सत्तापक्ष को फर्क पड़ता है और न ही विपक्ष को। बिना बहस और जवाबतलबी के विधेयक पारित हो जाएं तो सत्तापक्ष के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? दोनों ही सदनों में विपक्ष को भी संसद से बाहर सड़क और चुनाव की राजनीति के लिए अपने मुद्दों को धार देने का मौका मिल ही रहा है। दोनों ही एक-दूसरे को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, पर कौन कितना लोकतांत्रिक है, वह जनता बखूबी जानती है। दोनों सदनों के लगभग साढ़े सात सौ सांसदों के वेतन-भत्तों और सुख-सुविधाओं पर भी तो करदाताओं की गाढ़ी कमाई ही खर्च होती है। अगर ये सांसद संसदीय कार्यवाही और चर्चा की अपनी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह ही ठीक से नहीं कर रहे।

ब्रेड से बनाएं झटपट क्रिस्पी स्नैक्स, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का मन करे

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

अगर शाम की चाय के साथ कुछ स्वादिष्ट और झटपट बनाने का मन हो तो ब्रेड से तैयार होने वाले स्नैक्स अच्छा विकल्प हो सकते हैं। घर में मौजूद कुछ सामान्य सामग्री से आप कम समय में कुरकुरे और स्वादिष्ट नाश्ते तैयार कर सकते हैं।

ब्रेड पिज्जा टोस्ट-ब्रेड स्लाइस पर पिज्जा सॉस या टोमैटो सॉस लगाएं। इसके ऊपर बारीक कटी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ा चीज डालें। ऊपर से चिली फ्लेक्स और मिश्रित जड़ी-बूटियां डालकर तवे या ओवन में तब तक सेंकें, जब तक ब्रेड कुरकुरी और चीज पिघल न जाए।

ब्रेड पोटेटो बाइट्स-उबले आलू में बारीक प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक और पसंद के मसाले मिलाएं। ब्रेड को हल्का गीला कर उसमें आलू का मिश्रण भरें और छोटे आकार में तैयार

करें। इन्हें तवे पर थोड़े तेल में चारों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।

ब्रेड रोल-उबले आलू में नमक, लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा गरम मसाला मिलाएं। ब्रेड स्लाइस को हल्का गीला करके आलू का मिश्रण भरें और रोल का आकार दें। कम तेल में तवे पर सेंकने से भी अच्छे कुरकुरे रोल तैयार हो जाते हैं।

चीज कॉर्न टोस्ट- ब्रेड पर उबला हुआ स्वीट कॉर्न, चीज, प्याज और मसाले डालें। तवे पर ढककर कुछ

मिनट पकाएं। चीज पिघलने और ब्रेड के किनारे कुरकुरे होने पर इसे गरम-गरम परोसें। इन स्नैक्स को कम तेल में तवे पर तैयार किया जा सकता है।



स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।

खाना खाने के बाद

टहलना क्यों है जरूरी? शरीर को मिलते हैं ये फायदे



रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटना या लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना रोजमर्रा की आदत हो सकती है, लेकिन भोजन के बाद हल्की-फुल्की गतिविधि शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाती है। खासतौर पर भोजन के बाद थोड़ी देर सामान्य गति से टहलना पाचन और रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।

पाचन में मिल सकती है मदद- खाने के बाद हल्की चाल से चलने पर शरीर सक्रिय रहता है और पाचन प्रक्रिया को सहारा मिल सकता है। इससे पेट भारी लगने या असहजता की समस्या कुछ लोगों में कम हो सकती है।

रक्त शर्करा पर असर- भोजन के बाद शरीर में रक्त शर्करा बढ़ती है। हल्की शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं, जिससे भोजन के बाद रक्त शर्करा में होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

पेट फूलने और गैस में राहत- खाने के बाद थोड़ी देर चलने से शरीर की गतिविधि बढ़ती है, जिससे कुछ लोगों को गैस, पेट फूलने और भारीपन से राहत महसूस हो सकती है।

वजन प्रबंधन में उपयोगी-नियमित रूप से भोजन के बाद थोड़ी देर चलना रोजाना की कुल शारीरिक गतिविधि बढ़ाने का आसान तरीका है। हालांकि, केवल टहलने से वजन कम नहीं होता; संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी जरूरी हैं।

कितनी देर टहलें?- भोजन के बाद तेज दौड़ या भारी व्यायाम करने के बजाय आरामदायक गति से थोड़ी देर चलना बेहतर है। शरीर की क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार समय और गति तय करनी चाहिए। अगर भोजन के बाद बार-बार तेज पेट दर्द, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या अन्य असामान्य लक्षण हों, तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

सुबह खाली पेट पानी पीना कितना फायदेमंद? जानिए क्या कहता है विज्ञान

सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। इसे शरीर की सफाई, वजन घटाने और पाचन बेहतर करने जैसी कई बातों से जोड़ा जाता है। लेकिन हर दावे के पीछे मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण होना जरूरी नहीं है। असल में सुबह पानी पीने का सबसे बड़ा फायदा शरीर को पर्याप्त मात्रा में तरल उपलब्ध कराना है।

शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद- रातभर पानी न पीने के बाद सुबह पानी पीना शरीर में तरल की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। पर्याप्त पानी पीना सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी है।

पाचन में सहायक हो सकता है-पानी मल को नरम रखने में मदद करता है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कब्ज की समस्या से बचाव में मदद मिल सकती है। हालांकि, केवल खाली पेट पानी पीना ही बेहतर पाचन की गारंटी नहीं है।

वजन घटाने का दावा कितना सही?-सिर्फ सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर की चर्बी सीधे कम नहीं होती। हां, भोजन से पहले पानी पीने से कुछ लोगों में पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे कुल कैलोरी का सेवन कम हो सकता है।



क्या गुणगुना पानी ज्यादा फायदेमंद है?-गुणगुने पानी को लेकर कई स्वास्थ्य दावे किए जाते हैं, लेकिन सामान्य पानी की तुलना में गुणगुना पानी शरीर की "गंदगी" निकालने या तेजी से वजन घटाने के लिए अधिक प्रभावी है, इसका मजबूत प्रमाण नहीं है। इसलिए सुबह पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन इसे किसी चमत्कारी स्वास्थ्य उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। दिनभर पर्याप्त पानी पीना, संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधि ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

मानसून में कान का संक्रमण बढ़ सकता है परेशानी, पानी और खुजली को न करें नजरअंदाज

बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस दौरान कान में पानी जाने, पसीना और नमी लंबे समय तक बने रहने से कुछ लोगों में कान के बाहरी हिस्से में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। खासकर तैराकी करने वालों या बार-बार कान में पानी जाने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। कान में खुजली पहला संकेत हो सकता है- कान में लगातार खुजली, भारीपन, दर्द या कान के आसपास छूने पर संवेदनशीलता संक्रमण के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कुछ मामलों में कान से पानी या अन्य तरल पदार्थ निकलना भी शुरू हो सकता है। कान में पानी जाने पर क्या करें?- बारिश या नहाने के बाद कान के बाहरी हिस्से को मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे सुखाएं। कान के अंदर पानी निकालने के लिए माचिस की तीली, पिन, हेयरपिन या कॉटन बड डालने से बचें। इससे कान की त्वचा को चोट लग सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ईयरफोन और ईयरबड का इस्तेमाल भी सावधानी से करें- लंबे समय तक कान बंद रखने वाले उपकरणों के इस्तेमाल से नमी और गर्मी बनी रह सकती है।

क्या स्किन कैंसर दोबारा लौटने से रोक सकती है पर्सनलाइज्ड वैक्सीन? नई रिसर्च ने जगाई उम्मीद

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

कैंसर के इलाज में व्यक्तिगत उपचार की दिशा में तेजी से शोध हो रहा है। मॉडर्न और मर्क की विकसित की जा रही पर्सनलाइज्ड एमआरएनए आधारित थेरेपी इंटीसमेरान ऑटोजीन (V940) ने हाई-रिस्क मेलेनोमा मरीजों में उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं।

हालांकि, इसे अभी ऐसा इलाज नहीं कहा जा सकता जो स्किन कैंसर को हमेशा के लिए खत्म कर दे या दोबारा लौटने से पूरी तरह रोक दे। 2026 में पेश किए गए पांच साल के फॉलो-अप आंकड़े फेज-2बी KEYNOTE-942 अध्ययन से आए हैं, जिसमें सर्जरी के बाद



हाई-रिस्क स्टेज-3/4 मेलेनोमा वाले मरीजों में V940 को कीटूडा के साथ दिया गया। इस संयोजन ने अकेले कीटूडा की तुलना में कैंसर के दोबारा लौटने या मरीज की मृत्यु के जोखिम को 49 प्रतिशत कम किया। दूर के अंगों तक कैंसर फैलने या मृत्यु का जोखिम भी 59 प्रतिशत कम रहा।

इस थेरेपी की खासियत यह है कि इसे मरीज के अपने ट्यूमर की आनुवंशिक जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर कोशिकाओं में मौजूद खास बदलावों को पहचानने और उनके खिलाफ प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है

फिर बढ़ सकती है लोन की ईएमआई! महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरों पर सख्ती के संकेत

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

भारतीय रिजर्व बैंक की अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के मिनट्स ने कर्ज लेने वालों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि आरबीआई ने फिलहाल रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, लेकिन महंगाई का दबाव बढ़ने पर आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चेताया है कि अगर खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य लागतों में बढ़ोतरी व्यापक महंगाई में बदलती है, तो मौद्रिक नीति को सख्त करने की जरूरत पड़ सकती है। उप-गवर्नर पूनम गुप्ता ने भी कहा कि तीसरी तिमाही में महंगाई 5.9 प्रतिशत तक पहुंचने की स्थिति में ब्याज दर बढ़ाने का मामला बन सकता है।

महंगाई के आंकड़े भी दबाव की ओर इशारा कर रहे हैं। जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई, जबकि खाद्य महंगाई 5.52 प्रतिशत दर्ज की गई। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनका होम लोन, वाहन ऋण या अन्य कर्ज फ्लोटिंग ब्याज दर से जुड़ा है। अगर आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है और बैंक उसका असर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो ईएमआई बढ़



सकती है या कर्ज की अवधि लंबी हो सकती है। हालांकि अभी ईएमआई बढ़ना तय नहीं है। आरबीआई का अगला कदम महंगाई की दिशा और खाद्य-ईंधन कीमतों के असर पर निर्भर करेगा। फिलहाल संदेश साफ है—महंगाई काबू में नहीं आई तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर और बढ़ोतरी का जोखिम मजबूत हो सकता है।

निवा बूपा पर आईआरडीआई का एक्शन, छह महीने तक नए कारोबार केंद्र खोलने पर रोक

दैनिक “भास्करदर्पण”

www.dainikbhaskardarpan.com

निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पर बीमा नियामक आईआरडीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। नियामक ने कंपनी को छह महीने तक कोई नया कारोबार केंद्र या कार्यालय खोलने से रोक दिया है। यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2024-25 में निर्धारित प्रबंधन खर्च सीमा का पालन नहीं करने के मामले में की गई है। आईआरडीआई के अनुसार, बीमा कंपनियों के लिए प्रबंधन खर्च में परिचालन लागत के साथ एजेंटों और वितरकों को दिए जाने वाले कमीशन जैसे खर्च भी शामिल होते हैं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए इन खर्चों की निर्धारित सीमा का पालन करना जरूरी है। निवा बूपा के मामले में जांच के बाद पाया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक प्रबंधन खर्च अनुमत सीमा से 248.37 करोड़ अधिक था।

नियामक ने कंपनी से इस संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा था। कंपनी ने अपना जवाब आईआरडीआई के सामने रखा। इसके बाद 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश में कंपनी को नियमों का पालन न करने के लिए चेतावनी दी गई और छह महीने तक नए कारोबार केंद्र नहीं खोलने का निर्देश दिया गया। निवा बूपा का कहना है कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में निर्धारित खर्च सीमा का पालन किया है और मौजूदा वित्त वर्ष में भी नियमों के दायरे में रहने की दिशा में काम कर रही है।

कंपनी ने कहा है कि वह आदेश का मूल्यांकन कर रही है और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीमा क्षेत्र में खर्चों की सीमा सीधे कंपनियों की लागत संरचना और कारोबार विस्तार से जुड़ी होती है। अब देखना होगा कि निवा बूपा इस नियामकीय पाबंदी के बाद अपनी खर्च व्यवस्था और विस्तार रणनीति में क्या बदलाव करती है।

इथेनॉल की वजह से महंगी हो रही चीनी?

दिल्ली। चीनी की कीमतें पिछले एक महीने में तेजी से बढ़ी हैं। 20 जुलाई 2026 को 48.18 रुपए प्रति किलो रही चीनी 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। यानी पिछले एक महीने में करीब 15.6% की बढ़ोतरी (sugar price hike India) हुई है। कीमतों में इस उछाल के बीच इथेनॉल को लेकर उठ रहे सवाल पर सरकार ने साफ कहा है कि चीनी महंगी होने की वजह गन्ने से इथेनॉल बनाना नहीं है। मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन (LMT) रहने का अनुमान है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों ने शुरुआत में करीब 343 LMT का अनुमान लगाया था। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि अक्टूबर में नई क्रशिंग सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक (sugar dealer stock limit) मौजूद है। ग्लोबल मार्केट में महंगी हुई चीनी-चीनी की महंगाई सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। 2026-27 के लिए वैश्विक चीनी घाटा करीब 33 LMT रहने का अनुमान है। मौसम को लेकर चिंताओं ने भी सप्लाई आउटलुक को प्रभावित किया है। अंतरराष्ट्रीय चीनी कीमत 30 जून को \$474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को \$552 प्रति टन हो गई। यानी दो महीने से भी कम समय में 16% से ज्यादा उछाल (global sugar prices rise) आया। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल कार्यक्रम ने चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत की है। भारत सामान्य तौर पर 320-340 LMT चीनी बनाता है, जबकि घरेलू खपत करीब 280-290 LMT है।

शुक्रवार को करें ये 5 उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर हो सकती है आर्थिक तंगी

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा, दान और सेवा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं। हालांकि, इन उपायों का आधार धार्मिक मान्यताएं हैं, इन्हें धन की समस्या दूर होने की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।

1. विधि-विधान से करें लक्ष्मी पूजा-शुक्रवार को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। कमल या गुलाबी-सफेद फूल अर्पित कर खीर या मिठाई का भोग लगाने की परंपरा है।
2. शाम को घी का दीपक जलाएं-धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम के समय मां लक्ष्मी के



सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

3. सफेद वस्तुओं का दान करें-शुक्रवार को चावल, दूध, दही, चीनी या सफेद वस्त्र जैसी चीजें जरूरतमंदों को दान करना शुभ

माना जाता है। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और निस्वार्थ भाव से करना बेहतर है।

4. घर को साफ और व्यवस्थित रखें-धार्मिक मान्यता में स्वच्छता को मां लक्ष्मी के आगमन से जोड़ा गया है। इसलिए शुक्रवार को विशेष रूप से मुख्य द्वार, पूजा स्थल और रसोई की सफाई करने की परंपरा है।
5. किसी जरूरतमंद की मदद करें-किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में सेवा और विनम्र व्यवहार को विशेष महत्व दिया गया है।

ध्यान रखें: आर्थिक परेशानी केवल धार्मिक उपायों से दूर होने की गारंटी नहीं है। आय, खर्च, बचत और कर्ज की स्थिति को व्यवस्थित करना भी उतना ही जरूरी है।

ग्लोबल बाजार में HDFC बैंक का दमखम, 1.75 अरब डॉलर जुटाकर बनाया नया रिकॉर्ड

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक ने अंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजार में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बैंक ने अपनी गिफ्ट सिटी शाखा के जरिए 1.75 अरब डॉलर जुटाए हैं। यह राशि दो हिस्सों वाली डॉलर बॉन्ड बिक्री के माध्यम से जुटाई गई है और इसे किसी भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा अब तक का

सबसे बड़ा ऋण पूंजी बाजार जुटाव बताया जा रहा है। इस सौदे की खास बात यह है कि बैंक ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से इतनी बड़ी रकम ऐसे समय में जुटाई है, जब वैश्विक बाजार में ब्याज दरों और मुद्रा जोखिम को लेकर निवेशक काफी सतर्क हैं। मजबूत मांग के चलते एचडीएफसी बैंक को वैश्विक निवेशकों का भरोसा हासिल हुआ है। बैंक के मुताबिक जुटाई गई राशि का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा में कर्ज देने और सामान्य

बैंकिंग गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इससे बैंक की अंतरराष्ट्रीय कारोबार क्षमता और विदेशी मुद्रा आधारित वित्तपोषण को मजबूती मिल सकती है। इससे पहले जून 2026 में भी एचडीएफसी बैंक ने गिफ्ट सिटी स्थित अपनी इकाई के जरिए 75 करोड़ डॉलर का पांच वर्षीय डॉलर बॉन्ड जारी किया था। उस बॉन्ड पर 5.067 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर तय हुई थी।

18 साल के रिकॉर्ड का मतलब क्या?— इस

सौदे को लेकर सामने आई रिपोर्टों में इसे भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए करीब 18 साल में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड सौदा बताया गया है। हालांकि, इसे “भारतीय वित्तीय संस्था का अब तक का सबसे बड़ा ऋण बाजार जुटाव” कहना अधिक सटीक है। एचडीएफसी बैंक की यह सफलता भारत के गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिशों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत में कितनी ताकतवर हो रही है जेन-अल्फा की आवाज?

स्कूल की बदहाली पर सड़कों तक पहुंचे बच्चे

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

भारत में जेन-अल्फा अब सिर्फ डिजिटल दुनिया की पीढ़ी नहीं रह गई है। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई राज्यों में बच्चों का सड़क पर उतरना इस बदलाव का संकेत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छात्रों ने शिक्षकों की कमी, खराब शौचालय, पीने के पानी, पंखे और स्कूल की दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाई है।

उत्तर प्रदेश में सड़क तक पहुंचा गुस्सा-लखनऊ में करीब 250 छात्राओं ने स्कूल से



लगभग ढाई किलोमीटर मार्च कर शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की समस्या उठाई। वहीं आजमगढ़ में छात्रों ने शिक्षकों की कमी और फीस

से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। फतेहपुर में भी छात्रों के आंदोलन के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया।

मध्य प्रदेश में भी दिखा असर- भोपाल में छात्रों और अभिभावकों ने डीएमएस स्कूल के संभावित केंद्रीय विद्यालय में विलय के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्कूल की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की मांग उठाई।

आखिर इतनी ताकत कहां से आ रही है? इस पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत सूचना तक तुरंत पहुंच है। बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं

के वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इससे स्थानीय मुद्दे तेजी से सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर प्रदर्शन के बाद स्थायी सुधार होगा? जेन-अल्फा के ये आंदोलन सरकार और शिक्षा विभाग के लिए चेतावनी भी हैं। बच्चे महंगे संसाधन नहीं, बल्कि पढ़ने लायक स्कूल, शिक्षक, पानी, पंखा और सुरक्षित वातावरण मांग रहे हैं। अगर इन बुनियादी मांगों के लिए भी बच्चों को सड़क पर उतरना पड़े, तो सवाल केवल बच्चों की आवाज का नहीं, बल्कि स्कूल व्यवस्था की जवाबदेही का है।

भोपाल में फिर मिले 4 पॉजिटिव, फ्लू के नए एच-3 एन-2 वेरिएंट के 3 प्रमुख लक्षण

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

भोपाल। राजधानी में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। शहर में फिर चार मरीजों के संक्रमित मिलने की जानकारी सामने आई है। बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच श्वसन संबंधी संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। हालांकि, उपलब्ध ताजा सार्वजनिक स्रोतों में इन चार मामलों को किसी नए एच-3



एन-2 वेरिएंट से जोड़ने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। एच-3 एन-2 सहित इन्फ्लुएंजा संक्रमण में सामान्य तौर पर अचानक बुखार, खांसी और गले में खराश प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। इसके साथ शरीर में दर्द, थकान, सिरदर्द और नाक बहने जैसी शिकायत भी हो सकती है। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे

लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।

भोपाल में मानसून के दौरान वायरल और श्वसन संक्रमण को लेकर पहले से सतर्कता जरूरी है। स्थानीय स्वास्थ्य जोखिम के उपलब्ध संकेतों में भी इस समय बुखार संबंधी बीमारियों का दबाव दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लगातार या तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी या लगातार बढ़ती खांसी को सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज न करें। संक्रमित व्यक्ति भीड़ से दूरी बनाए और चिकित्सकीय सलाह के बिना दवाओं का सेवन न करें।

सवाल यह है कि भोपाल में सामने आ रहे मामलों की वास्तविक संख्या कितनी है और क्या स्वास्थ्य विभाग इन संक्रमित मरीजों के नमूनों की जीनोम या विस्तृत जांच कर नए वेरिएंट की पुष्टि कर रहा है?

विधानसभा में भर्ती व्यवस्था बदलने की तैयारी, पीएससी से होगी अफसरों की भर्ती?

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में करीब 30 साल पुरानी भर्ती व्यवस्था में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अवर सचिव, उप सचिव और अपर सचिव स्तर के पदों पर नियुक्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने के विकल्प पर मंथन चल रहा है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाना बताया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पीएससी जैसी स्वतंत्र चयन संस्था के माध्यम से भर्ती कराने का विकल्प सामने आने से व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव है। माना जा रहा है कि इससे योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा और नियुक्तियों में पक्षपात या सिफारिश जैसे आरोपों की गुंजाइश कम हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी प्रशासनिक दक्षता और निष्पक्षता बनाए



रखने के लिए प्रमुख पदों पर भर्ती पीएससी के माध्यम से कराने के विकल्प पर विचार किए जाने की बात कही है। हालांकि अंतिम निर्णय होने से पहले भर्ती नियमों, पदों की प्रकृति और विधानसभा सचिवालय की संवैधानिक स्वायत्तता से जुड़े पहलुओं का परीक्षण जरूरी होगा। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो विधानसभा सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव होगा। सवाल यही है कि क्या नई व्यवस्था केवल कुछ चुनिंदा पदों तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में सचिवालय की अन्य नियुक्तियों के लिए भी प्रतियोगी चयन प्रक्रिया का रास्ता खुलेगा।

4338 बच्चों की सेहत पर संकट, 44 अस्पताल में भर्ती

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

बालाघाट। जिले में बैगा जनजाति के बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में बच्चों के स्वास्थ्य प्रभावित होने की सूचना के बीच 44 बच्चों के अब भी अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आई है। कुल 4338 बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे का आंकड़ा सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था और उपचार की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि प्रभावित बच्चों की संख्या इतनी बड़ी है तो बीमारी की शुरुआती पहचान, तत्काल उपचार और दूरस्थ बैगा बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी रही? आदिवासी अंचलों में कुपोषण, साफ पानी, स्वच्छता और समय पर



चिकित्सा सुविधा पहले से ही बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में बच्चों में बीमारी का फैलाव केवल चिकित्सा व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की क्षमता की भी परीक्षा है। अस्पतालों में भर्ती बच्चों की स्थिति पर लगातार निगरानी जरूरी है। साथ ही जिन हजारों बच्चों की स्वास्थ्य जांच हुई है, उनकी नियमित निगरानी और घर-घर स्वास्थ्य परीक्षण

की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। प्रशासन के सामने अब केवल मरीजों का इलाज कराने की चुनौती नहीं है। 4338 बच्चों के आंकड़े की वास्तविक स्थिति, बीमारी का कारण, प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करना भी जरूरी है।

नए संसद भवन में क्यों नहीं लगता अपनापन?

शशि थरूर बोले- 'बेजान कॉन्फ्रेंस सेंटर' जैसा

दैनिक "भास्करदर्पण"

www.dainikbhaskardarpan.com

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नए संसद भवन की बनावट और वहां सांसदों के बीच संवाद को लेकर सवाल उठाए हैं। 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान थरूर ने नए भवन को "बेजान कॉन्फ्रेंस सेंटर" जैसा बताते हुए कहा कि पुराने संसद भवन में जो अपनापन और सहजता महसूस होती थी, वह नए भवन में कम दिखाई देती है। थरूर के मुताबिक पुराने सदन की बनावट ऐसी थी, जहां सांसद एक-दूसरे के करीब रहते थे और सदन के बाहर भी अनौपचारिक बातचीत के मौके आसानी से मिल जाते थे।

इसके उलट नए भवन में बैठने की व्यवस्था पंखे जैसी आकृति में है, जिससे सांसदों के बीच दूरी का

अहसास होता है। उन्होंने इस भौतिक दूरी को मौजूदा राजनीतिक ध्रुवीकरण से भी जोड़कर देखा। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति केंद्रीय कक्ष के अभाव को लेकर है। पुराने संसद भवन का केंद्रीय कक्ष सांसदों, पूर्व सांसदों, पत्रकारों और संसद से जुड़े लोगों के बीच अनौपचारिक मुलाकात और बातचीत का महत्वपूर्ण स्थान था। थरूर का मानना है कि नए परिसर में ऐसी जगह की कमी ने विभिन्न दलों के नेताओं के बीच सहज संवाद और मेलजोल को प्रभावित किया है। हालांकि थरूर ने नए भवन की कुछ व्यावहारिक खूबियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने माना कि पुराने भवन में सीटों और गलियारों की व्यवस्था के कारण आने-जाने में परेशानी होती थी, जिसे नए भवन में बेहतर किया गया है।